RAJYA SABHA

Friday, the 22nd March, 2002/1 Chaitra, 1924 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि क्लीनिक

*281. प्रो. एम. एम. अग्रवाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 दिसम्बर, 2001 के "हिन्दुस्तान" में "प्रति वर्ष पांच हजार कृषि क्लीनिक खोलने का फैसला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन क्लीनिकों के माध्यम से किसानों को कृषि से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त क्लीनिक देश में कब तक काम करना शुरू कर देंगे?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) "कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना" नामक एक नई स्कीम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से हाल ही में आरंभ की गई है। इस स्कीम में कृषि स्नातकों और कृषि से संबद्ध विषयों में स्नातकों को नाबार्ड से पुनर्वित्त के साथ बैंक वित्त के माध्यम से स्व-रोजगार आधार पर चिन्हित कार्यकलापों में प्रतिवर्ष लगभग 5000 कृषि-क्लीनिकों/कृषि व्यापार उद्यमों की स्थापना में सहायता करने का प्रस्ताव है। कृषि क्लीनिक और कृषि-व्यापार उद्यम स्थापित करने में रुचि रखने वाले कृषि स्नातकों को उद्यमिता और व्यापार प्रबंध के क्षेत्रों में और कार्यकलाप के चुने गए क्षेत्रों में दक्षता सुधार के लिए दो से तीन महीनों का आरंभिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ उठाने का विचार रखने वाले स्नातकों को उनके परियोजना प्रस्तावों के स्वीकार होने पर प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने की शर्तों के अनुसार बैंक से

अनुमान है जिसमें प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा है और पांच अथवा अधिक स्नातकों द्वारा एक उद्यम के लिए सामूहिक तौर पर अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है। इस स्कीम में इन कृषि-क्लिनिकों और कृषि-व्यापार केन्द्रों के माध्यम से किसानों के लिए विस्तार और परामर्शी सेवाओं, मृदा तथा आदान परीक्षण सेवाओं तथा अन्य समर्थन सेवाओं के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। कृषि-क्लीनिक और कृषि व्यापार उद्यम अपना कार्य पात्र कृषि स्नातकों द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त करने और अपने उद्यम स्थापित करने के बाद आरंभ करेंगे।

Agricultural Clinics

†*281. PROF. M.M. AGARWAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn towards the news-item published in Hindustan of 23rd December, 2001 under the caption, "Prati varsh paanch hazar krishi klinic kholne ka faisla";

(b) if so, the details of the proposal;

(c) whether Government would also provide agriculture related training to farmers through these clinics; and

(d) if so, by when the said clinics would start functioning in the country?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (d) A new Scheme "Establishment of Agri-clinics and Agri-business Centres" has recently been launched in collaboration with National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). The scheme proposes to assist agriculture graduates and graduates in subjects allied to agriculture in setting up of around 5,000 Agri-clinics/Agri-business ventures per year in identified activities through Bank finance with refinance from NABARD on self employment basis. Start up training of two to three months in the areas of entrepreneurship and business management as well as for skill improvement in the chosen area of activity will also be provided to agricultural graduates interested in setting up agri-clinics and agri-business ventures. Graduates who propose to avail the benefit of the Scheme will be given bank finance on priority sector lending terms on acceptance of their project proposals. The average cost of an individual venture is estimated to be around Rs. 5 lakhs,

†Original notice of the question was received in Hindi.

with a maximum limit of Rs. 10 lakhs per individual, and the group ceiling of Rs. 50 lakhs for a venture by five or more Graduates. The scheme envisages provision of extension and consultancy services, soil and input testing services and other support services for the farmers through these agri-clinic and agri-business centres. The agri-clinic and agri-business ventures would start operations after the eligible agriculture Graduates are able to obtain loans from the Banks and set up their ventures.

प्रो. एम. एम. अग्रवाल: आदरणीय सभापति जी, हालांकि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में 23 दिसम्बर, 2001 को प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह मंजूर किया है कि सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि पांच हजार एग्री-क्लीनिक खोले जाएंगे, जिसका पूरा इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह एग्री-क्लीनिक खोले नहीं गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो इसमें लिखा है कि एग्री-क्लीनिक सेंटर बैंक और नाबार्ड की मदद से खोले जाएंगे तो इसमें जो फाइनेन्स की बात है यह फाइनेन्स कब तक मिलेगा और कब तक यह एग्री-क्लीनिक खुल जाएंगे? इसमें यह कहा गया है कि जो इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, वह स्नातकों को दी जाएगी। मेरा प्रश्न यह है कि इससे किसानों को क्या लाभ होगा? वैसे मंत्री जी खुद ही किसानों से बड़ा लगाव रखते हैं, बड़े उदार हैं और चाहते हैं कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। तो इस क्लीनिक के माध्यम से किसानों के लिए क्या किया जा रहा है?

श्री अजित सिंह: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि इस स्कीम का काफी पहले एनाउन्समेंट हुआ था, लेकिन इसकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम को ठीक तरह से तैयार करना था, जो अब तैयार हो गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, इन्हें बताने में मुझे प्रसन्नता होगी कि इसकी शुरुआत राजस्थान में 9 अप्रैल से हो रही है।

प्रो.एम.एम. अग्रवाल: माननीय सभापति जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो उदारीकरण का दौर चल रहा है, इसका सीधा असर किसान पर पड़ रहा है। उसकी जो प्रोड्यूस है वह मार्केट में नहीं बिकती है, उसे इनफीरियर बताया जाता है, इम्पोर्ट बहुत हो रहा है यानी कि किसान की हालत गिर रही है, वह कमजोर हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उसकी हालत को सुधारने के लिए सरकार क्या तरीके इस्तेमाल कर रही है?

श्री अजित सिंह: माननीय सभापति जी, मूल प्रश्न एग्री-क्लीनिक के बारे में है। किसानों की स्थिति सुधारने के संबंध में माननीय सदस्य की चिंता ठीक है, चिंता होनी भी चाहिए, इसकी हम सबको चिंता है और उसके लिए बहुत से कदम सरकार उठा रही है। लेकिन, यह सवाल एग्री क्लीनिक के बारे में है और एग्री क्लीनिक के पीछे मकसद यही है कि जो आज साइंस और टैक्नोलोजी में नये तरह के बीज या नई तरह की दूसरी चीजें आ रही हैं, वह किसान तक पहुंचे।...(व्यवधान)...

डॉ. एम.एम. अग्रवाल: मंत्री जी आप तो किसानों से जुड़े हुए हैं आप जानते हैं कि उनको सही खाद नहीं मिल रहा है। वह क्या करें? इस एग्री-क्लीनिक का डायरेक्टली मतलब यह था कि दूसरे किसान को हेल्प हो।

श्री अजित सिंह: सर, किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, उनकी सॉयल भी टेस्ट हो, सब प्रकार का टेस्ट हो, इसी के लिए यह स्कीम बनाई गई है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इसमें आएंगे। वह किसानों तक सुविधा पहुंचाएंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। यह सरकार की जो एक्सटेंशन सर्विस है उसका सप्लीमेंट है, उसमें मदद करने के लिए है।

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि खेती के लिए एग्री-क्लीनिक खुल रहा है। अगर तम्बाकू से कैन्सर होता है तो कैन्सर अस्पताल खुलने के बजाय तम्बाकू का सेवन बंद होना चाहिए, जो उपयुक्त है। किसानों में हरी खाद अब कोई लगाता नहीं, कम्पोस्ट खाद कोई लगाता नहीं, किसान को जो पानी कुएं से, जोहड़ से, तालाब से, नाले से, पोखर से मिलता था वह सब पट गया, तो पानी मिलता नहीं, बिजली मिलती नहीं, कीटनाशक दवाइयां मिलती नहीं, सस्ते और अच्छे बीज समय पर किसान को मिलते नहीं, उनको उपयुक्त यंत्र मिलते नहीं, जो उसको खेती की ज्यादा कोस्ट आफ प्रोडक्शन आती है उस के अनुसार उसे सही मूल्य लागत खर्चे के साथ समय पर मिलता नहीं,... समय पर उसका पैदा किया हुआ माल बाजार में नहीं बिकता। ये बीमारियां पहले से जो लगी हुई हैं, उनका इलाज किया जाए, इन फर्जी क्लीनिकों के बजाए तो वह ज्यादा उपयुक्त होगा। इसके अलावा अच्छी जमीन, खेती की जमीन, तीन फसला जमीन इंडस्ट्री में जा रही है, सड़क में जा रही है, अस्पताल में जा रही है, मकान में जा रही है और इस प्रकार तमाम अच्छी जमीन खराब होती जा रही है। पहाड़ों से मिट्टी आ रही है, पत्थर आ रहे हैं, पानी रिस रहा है, जमीन खारी हो रही है ....

श्री सभापति: आप सवाल कीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी, मेरा सवाल यह है कि ये फर्जी क्लीनिक बनाने के बजाए, जो किसान का सही इलाज है, जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है, वह इलाज उनसे होना चाहिए और किसान की सब्सिडी कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा मिलनी चाहिए, इस बारे में मंत्री जी आपका क्या ख्याल है?

श्री अजित सिंह: सभापति जी, किसानों की समस्याएं माननीय सदस्य ने बताई हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सब्सिडी घटाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है और हम चाहेंगे कि माननीय सदस्य का सहयोग भी सब्सिडी को बनाए रखने में मिलता रहे। यह जो क्लीनिक के बारे में आपने कहा है, तो कृषि की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए और कृषि उत्पादों की

क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर यह समस्या ठीक हो जाए तो बहुत सी समस्याओं का निदान हो सकता है, जिनके बारे में आपने कहा है। यह एग्री क्लीनिक इसीलिए हैं कि नई तकनीक कैसे किसानों तक पहुंचे, किस तरह से वे टैस्ट करें, यह सब ऐग्रीकल्चर ग्रेजुएट उन्हें बताएंगे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और यह उसी दिशा में एक कदम है।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति महोदय, कृषि मंत्री जी ने जो 'कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना' का विचार रखा है और उसको राजस्थान में शुरू करने जा रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें कई बातें ऐसी हैं जिनका कि जब तक विस्तार से पता नहीं चले कि वे किस प्रकार से क्या करना चाहते हैं, तब तक इस स्कीम का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है और ग्रेजुएट्स को जो काम मिलने की बात इन्होंने कही है, वह भी उन्हें नहीं मिल सकता है। जैसे माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि 'इस स्कीम का लाभ उठाने का विचार रखने वाले स्नातकों को उनके परियोजना प्रस्तावों के स्वीकार होने पर प्राथमिकता क्षेत्र की ऋण देने की शर्तों के अनुसार बैंक से वित्त प्रदान किया जाएगा'। अब इसमें किस प्रकार से वह परियोजनाओं को स्वीकृत कराए, फिर बैंक से पैसा ले, यह कुछ नहीं है। ट्रेनिंग के बारे में भी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वह राजस्थान में शुरू होने वाली है। तो क्या यह एक ही ट्रेनिंग कैम्प है या एक ही जगह से शुरू करके वे पूरे देश की खेती की व्यवस्था कर सकते हैं या ऐसे क्लिनिकों की व्यवस्था कर सकते हैं?

तीसरी बात, जैसा माननीय अग्रवाल जी ने अभी किसानों का सवाल पूछा है, मैं कहना चाहता हूं कि खेती के सुधार के साथ खेती की पैदावार बढ़ने का भी सवाल जुड़ा हुआ। इसलिए मेरा पूछना यह है कि उस पैदावार का आप क्या करेंगे क्योंकि आपके यहां तो पिछले दिनों का ही इतना स्टॉक जमा हो रहा है? मेरा मानना है कि इसके साथ-साथ हमें यह भी सोचकर चलना पड़ेगा कि हम किसानों को उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य दिला सकें, आज तो उनको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इस स्कीम के साथ-साथ यह भी जुड़ा होना चाहिए कि हम उनके लाभप्रद मूल्य की बात सोचकर चलें और वह उनको मिलना चाहिए क्योंकि ये अलग चीज़ें नहीं हैं।

तो मैं माननीय मंत्री जी से एक तो परियोजना के संबंध में जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से यह परियोजना होगी, वे इसको विस्तार से बताने की कृपा करें और यदि अभी उत्तर न दे सकें तो बाद में सबके पास इस परियोजना का प्रारूप भेजने का कष्ट करें?

श्री अजित सिंह: सभापति जी, यह परियोजना 9 अप्रैल को राजस्थान से शुरू हो रही है। माननीय सदस्य को चिंता थी कि बहुत समय हो गया है, यह कब शुरू होगी, तो मैं उनको बता दूं कि यह खाली एक जगह से शुरू नहीं होगी, अगले महीने-दो-महीने में हमने 17 जगहें ऐसी तय की हैं, जहां से यह ट्रेनिंग शुरू हो सकती है और इसको और आगे भी बढ़ाया जाएगा। यह दो-अढ़ाई महीने की ट्रेनिंग होगी। जहां तक बैंक के लोन का सवाल है, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि

बैंक से अगर लोन लेना है तो बैंक से योजना तो उनको स्वीकृत करानी ही पड़ेगी। बैंक पैसा देगा तो पहले वह योजना को तो देखेगा ही।

एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया कि किसान को उसकी उपज का सही पैसा नहीं मिल रहा है, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ उपजों में यह समस्या है, सबको मालूम है और एम.एस.पी. भी सरकार समय-समय पर बढ़ाती रही है ताकि टर्म्स आफ ट्रेड, किसानों के हक में और आ जाए। सरकार यह योजना भी चला रही है कि डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। जिन फसलों में किसानों को ज्यादा पैसा मिल सकता है, उनमें हम एम.एस.पी. ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे उनमें जाएं-तिलहन में जाएं, दालों में जाएं, फूड ग्रेन्स में जाएं और इसके लिए भी सरकार की योजना है।

पानी की समस्या है, जोहड़ों की समस्या है तथा और बहुत सी समस्याएं हैं उसके लिए तरह-तरह की बहुत सी सरकार के पास स्कीमें हैं। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे किसानों के सामने चुनौती आने वाली है, वह यह है कि जो नई तकनीक आ रही है और जिसको साईंटिस्ट तैयार कर रहे हैं वह दो एकड़ तक के किसानों के पास किस तरह और कैसे पहुंचे, यह एग्री क्लीनिक उसी दिशा में एक कदम है।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, the need of the hour is to improve the productivity of the farming community in India, as the Minister himself has admitted. But I do not know to what extent the parallel services that are being created by these clinics will serve the purpose. I want to put one specific question to the Minister. Is the Government really interested in improving the productivity of the farmers in this country? To quote one example of this condition, cotton farmers are committing suicides continuously in this country, especially, in Andhra Pradesh, because the cost of pest control is exorbitantly high and the productivity is very low. Other countries like America, China and Mexico, which have got the same environmental conditions as India has got, are producing by using BT cotton seeds, with 60 per cent extra productivity, and 60 per cent of the pest control cost is cut. When such is the case, what prevents this Government from introducing these seeds to the farming community here? The farming community will get benefited. The farmers are making representations for the past couple of years. Trial runs have been done. Three crops have been taken for experiment. The reports have been submitted. They are in favour of it. Just because some influential multinational NGOs are opposing it, it has been stalled. I want to know whether the Minister can assure the House that if the reports of the scientific community are favourable, the Government is prepared to give clearance to introduce these seeds in India, so that the farmers, particularly in Andhra Pradesh, get benefited by them.

SHRI AJIT SINGH: When introducing any genetically modified seed or food, one has to be very careful. There is biodiversity. We have different climatic conditions in our country. We have to test it very extensively. Tests have been conducted. In the Environment Ministry, there is a Committee which looks at the tests, from the Technology, Agriculture and the Health points of view. The hon. Member is right that the reports have been submitted. They will be meeting very shortly. Based on the reports, on the test results that have come, if they are positive. It will be permitted. If there are more tests needed, they will be done because, as I mentioned, on this subject, one has to test everything very carefully.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: For three years, the Indian farmers have been deprived of this advantage.

श्री बालकवि बैरागी: धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से कुछ जानकारी चाहूंगा और वह देश के हित में भी होगी और हमारे ज्ञानवर्धन में भी काम आएगी। आपने कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि किसानों के पढ़े-लिखे बच्चों या जो खेती किसानी से जुड़ कर के, पढ़ लिख कर के ग्रेज्युएट हो गए हैं, उनको भी रोजगार धंधे में लगाने की दिशा में हम सोचें। यह आपका शुभ संकल्प है और इसके लिए आपने अच्छी स्कीम तैयार की है। इसके लिए पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन इसमें कुछ संदेह पैदा होता है। मैं अपने प्रश्न के पार्ट ए, बी, सी, करूं, उससे बेहतर है कि मैं अपनी जिज्ञासा एक साथ आपके सामने व्यक्त कर दूं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण लेने के लिए जो विद्यार्थी जाएंगे और जब वह वापिस लौटेंगे तो क्या आप उनको सार्टिफिकेट देंगे, डिग्री देंगे, डिप्लोमा देंगे या क्या करेंगे, जिससे वे पहचाने जाएं कि ये वहां से लौटे हैं? उनकी विशेष पहचान किस तरह से बनेगी, इस पर आपने क्या कुछ सोचा है? दूसरे, आपने 5000 कृषि क्लीनिक खोलने का संकल्प किया है। तो राज्यवार कितने राज्यों में कहां-कहां ये क्लीनिक खुलेंगे और इसका कोई चार्ट आपके पास तैयार है? अगर हो तो आप उसको देने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, मेरी अगली जिज्ञासा यह है कि एक व्यक्ति के उद्यम की औसत लागत का अनुमान लगभग 5 लाख रुपए है जिसमें प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए अधिकतम सीमा है और 5 अथवा अधिक स्नातकों द्वारा एक उद्यम के लिए सामूहिक तौर पर अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है। यह जो आपने इसमें प्रावधान रखा है, यह जो परिकल्पना रखी है, इसके देशव्यापी प्रचार की कोई व्यवस्था आपने की है या नहीं? मेरा अंतिम निवेदन आपसे विशेष है कि एक तरफ हम उन्नत बीज के माध्यम से देख रहे हैं इतनी अधिक पैदावार हमारे किसानों ने की है कि हमारे खाद्यान्न भंडार भरे हुये हैं और उन्हें इसका उचित मूल्य नहीं

मिल रहा है। लेकिन एक विसंगति की तरफ आपका ध्यान गया होगा क्योंकि आप स्वयं कृषि से जुड़े हुये हैं। माननीय सभापति महोदय, वह यह है कि हमारे देश में खेतिहर मजदूर कम होते चले जा रहे हैं। आज यह स्थिति गांव-गांव में पैदा हो गई है कि जो किसान है वह अपने ही खेत में मजदूर हो गया है। इसमें विसंगति यह है कि उसकी मजदूरी में गिरावट आती चली जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरों की संख्या को कम होने से रोकना और जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो उद्यमशील होना चाहते हैं, इनके संतुलन को बनाने के लिए क्या आपके मंत्रालय ने कोई योजना बनाई है? अगर बनाई है तो कृपया करके उस पर विस्तार से प्रकाश डाल दें तो मैं आपका इस देश पर बहुत बड़ा उपकार मानूंगा। धन्यवाद।

श्री अजित सिंह: सभापति महोदय, हम ट्रेनिंग के अंत में सर्टिफिकेट जरूर देंगे, जिसके बारे में माननीय सदस्य जी ने कहा है। जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी की है उनके पास कोई पहचान पत्र होना जरूरी है। उनके पास कुछ पहचान पत्र होना चाहिए जिससे कि व बैंक वगैरह से लोन लेने के लिए बात करें तो उन्हें लोन मिल सके। कुछ क्षेत्रों में ज्यादा उत्पादन हो रहा है उसकी चिंता माननीय सदस्य को है, उसके लिए डायवर्सीफिकेशन वगैरह की तरफ सरकार ध्यान दे रही है। अब बहुत सी जोत छोटी होती चली जा रही हैं इसलिए किसान खुद फसल पैदा कर रहा है। इसका तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। ...(व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति महोदय, जो सज्जन इस समय कृषि मंत्री के रूप में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, वे इस देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता, किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र हैं, जिन्होंने किसानों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। आपसे निराशा का उत्तर और निराशा का संकल्प यह सदन और देश सुनना पसन्द नहीं करेगा, इसलिए आप सोच-समझकर के उत्तर दीजिएगा।

श्री अजित सिंह: सर, मैं तो यही कह रहा था कि जो माननीय सदस्य ने खुद आब्जर्वेशन किया है कि जोत छोटी होती चली जा रही हैं इसलिए किसानों को ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं है। साथ ही बहुत सी नई तकनीक भी आ रही है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर मजदूरों की जरूरत पड़ती है। यह बात भी सही है कि बहुत से क्षेत्रों में मजदूर नहीं मिलते हैं, दूसरे प्रदेशों से मजदूर आकर खेती में काम कर रहे हैं। ऐसा तो हर क्षेत्र में होता है। जहां पर आदमी को काम मिलेगा, वह वहां पर जायेगा, चाहे इंडस्ट्री हो या कोई दूसरा काम हो। माननीय सदस्य क्या चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आया है।

श्री बालकवि बैरागी: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार के माननीय श्रम मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में इसी सदन में बताया कि देश

के विकास में हमारे यहां खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत 27 था, वह अब घटकर के 13 प्रतिशत हो गया है। हमारे यहां 14 प्रतिशत मजदूरों का पार्टिसिपेशन कम हुआ है। हमारा अधकचरा, आधा पढ़ा-लिखा, करीब-करीब अनपढ़ मजदूर खेत से निकल कर सड़क पर आ कर के खड़ा हो गया है। जो विद्यार्थी पढ़-लिख कर निकले हैं, उनके सामने तो कुछ अवसर हैं कि वे विज्ञान के क्षेत्र में जा सकते हैं, आईटी के क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन जो अधेड़ मजदूर खेत से निकल करके सड़क पर आकर खड़ा हो गया है तो क्या उसके लिए आपके पास कोई विचारशील परिकल्पना है? इसके बारे में हमारी बहुत बड़ी चिंता है और मैं इसमें आपको भागीदार बनाना चाहता हूं।

श्री अजित सिंह: सभापति महोदय, हमारे देश में बेकारी की समस्या बहुत है। माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है लेकिन एग्री क्लिनिक के पीछे उद्देश्य यह है कि किसानों को नई तकनीक, सॉयल इन-पुट्स वगैरह की टेस्टिंग की सुविधा ब्लॉक से मिल सके। यह सवाल उससे संबंधित है। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है - वह समस्या हर क्षेत्र में है, पढ़े-लिखे लोगों में भी है, जो बिना पढ़े लोग हैं, उनके सामने यह समस्या है। यह समस्या सरकार की जानकारी में है और समय-समय पर सरकार इसके लिए योजनाएं बनाती है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, माननीय सभापति जी, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री बालकवि बैरागी: सर, पांच हजार में से कितने...

श्री सभापति: बस हो गया। अब बस हो गया। अब हो गया। आपने चार सवाल किए हैं।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: सभापति महोदय, सवाल की उत्पत्ति तब हुई जब दो दिसम्बर को अखबार में एक खबर छपी कि प्रतिवर्ष पांच हजार कृषि क्लीनिक खोलने का फैसला लिया गया है। वैसे समय-समय पर केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकारों ने स्टेट फार्म कारपोरेशन भी बनाये हैं। उसमें भी सारे क्लीनिक्स की व्यवस्था थी पर वे सारे के सारे डूब गए और वे आज बिक्री या ऑक्शन के कगार पर हैं। मुझे आपके जवाब से यह समझ आया कि आप प्राइवेट क्लीनिक खोलने में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की मदद करेंगे। उनको ऋण दिलाने की व्यवस्था करेंगे। ऋण दिलाना आसान होगा, जगह दिलाना भी आसान होगा लेकिन जो डाटा चाहिए, उसके लिए जो बैकअप चाहिए, जैसे कि हैदराबाद में इक्रीसेट ने रिसर्च करके रेनफेड एरिया में, इरिगेशनफेड एरिया में या ड्रिप इरिगेशनफेड एरिया में किस तरह की फसल हो सकती है और कितनी हो सकती है, इस पर काम किया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जरूर जानना चाहूंगा कि आज एक माहौल चल पड़ा है और इनऑर्गेनिक खाद के खिलाफ ऑर्गेनिक खाद की लड़ाई शुरू हो गई है। सारे विश्व में ऑर्गेनिक खाद के फेवर में अब यह बात उठने लगी है कि

इनऑर्गेनिक खाद या जिस फसल पर पेस्टिसाइड्ज का प्रयोग ज्यादा होता है, वह शरीर और मानव जाति के लिए हानिकारक है। इसलिए उस पर रोक लगने लगी है और बाहर तो, विदेशों में तो इनकी दुकानें अलग हो गई हैं, शेल्फ तक अलग हो गए हैं। इनऑर्गेनिक खाद जब लागू हुई थी तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ-साथ हमें फसल बढ़ानी थी। लेकिन ऑर्गेनिक खाद से हम फसल कितनी ज्यादा कर सकेंगे, उसके लिए क्लीनिक को जो फीडबैक चाहिए, रिसर्च के लिए जो डाटा चाहिए, क्या वह आप इन इंजीनियर्स को उपलब्ध कराएंगे या उनको नाम मात्र ऋण दिला देंगे जिससे कि आने वाले दिनों में वे इतने रुग्ण हो जाएं कि वे क्लीनिक चला न सकें, किसान से पूरी फीस न ले सकें और जो डाटा उनको चाहिए, अगर उनको बाज़ार से या मल्टीनेशनल से खरीदना पड़े तो वह बहुत महंगा पड़े और उनको रॉयल्टी पे करनी पड़े। तो क्या सरकार कृषि अनुसंधान केंद्रों में जो डाटा उपलब्ध हैं, वह इन ग्रेजुएट इंजीनियर्स को उपलब्ध कराएगी?

श्री अजित सिंह: एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए ही यह स्कीम है तो हम आशा करते हैं कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को इस डाटा का महत्व पता है और कहां-कहां वह डाटा मिल सकता है, इसके बारे में भी उनको पता है और सरकार इसमें पूरी तरह से उनकी मदद करेगी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक खाद के बारे में भी माननीय सदस्य ने चिंता जताई है। अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में इनऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल काफी कम है। ऑर्गेनिक खाद हमारे देश में अभी भी बहुत हो रही है और उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, यह हम मानते हैं और इसकी तरफ सरकार कुछ कदम भी उठा रही है। बाकी डाटा के बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा, तो एग्री क्लीनिक्स सक्सेसफुल हों, वे किसानों की मदद कर सकें, इसके लिए सरकार से जो भी मदद संभव हो सकती है, वह करेगी।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: The primary problem of the agricultural community—the Minister understands it—is availability of seeds, fertilizers and pesticides. I am not going into the issue of remunerative prices. The problem in this country is that a vast number of companies or a vast number of people are engaged in producing spurious seeds, pesticides and other things. In Andhra Pradesh, it has been reported that some companies, in the name of multinational companies or as the agencies of multinational companies, are producing seeds and pesticides and giving them to the peasants; with the result that the peasants are in a serious trouble. Some measures should be taken to check such things. That is the first point.

The second point is whether these clinics will be run exclusively by graduate engineers or agricultural graduates or it will be run in cooperation with the Government. I would like to know whether the Government would

have any stake in those clinics. This has to be clarified. What stake would the Government have in those clinics?

SHRI AJIT SINGH: Sir, the Government's stake is there, in the sense that we are going to get them loans through Banks and we will give them training. In a larger context, the stake is that we want the information to reach the farmers through these clinics. These people would be trained in order to test seeds, pesticides, fertilizers and soil fertility. We will ensure that these agri-clinics get all the facilities for testing seeds, fertilizers and soil. That is one of the purposes. If a farmer wants through these agri-clinics, he should be able to get these things tested.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Mapping of soil and land could not be done because of diversification. In some areas we have one kind of soil and in some other areas we have a different kind of soil. Will it be left to these clinics?

SHRI AJIT SINGH: Our soil may be diverse, but that information is available today. We have been doing intensive farming. Today, soil fertility is a very big concern of the Government of India. I do agree that we do not have proper testing facilities which we should have had. Before using seeds and fertilizers, our farmers want their soil should be tested. They are very anxious. One of the purposes behind agri- clinics is that these facilities should reach the farmers.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: The farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh have made the country self- sufficient. But, instead of giving awards to these farmers, these farmers are being punished for producing more. A lot of problems have arisen. As a result, a large number of farmers are committing suicides. This occupation is crumbling. The farmers are groping in the dark in the absence of any guidance for crop rotation, etc. Will these clinics be able to provide some guidance to these farmers so that they can shift from the present crops like wheat, paddy, cotton, maize, etc., to some other crops, to be able to survive economically?

SHRI AJIT SINGH: Sir, the Hon. Member has talked about the problems faced by successful farmers. Success brings its own problems. The Government has some other schemes also for diversification, crop rotation, horticulture, etc. These agri-clinics will have to concentrate on these aspects also. I expect that the entrepreneurs will address to these problems. If they want to have agri-

clinics in Punjab, they will have to look at these aspects. That is one of the purposes. Apart from that, the Government is also encouraging diversification in different ways.

Another base station in Antarctica

*282. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the Minister of OCEAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether India propose to set up another permanent base station in Antarctica;

(b) if so, the details thereof, and

(c) the target for setting up the station?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF OCEAN DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) Yes, Sir. A proposal to set up another research station in Antarctica is under consideration by the Government of India and the details are being worked out.

SHRI K.M. SAIFULLAH: Sir, I had put three questions to get the details in regard to the base station in Antarctica. But the hon. Minister has given a one-sentence reply saying that the details are being worked out. Anyhow, I would like to put my supplementary. Is it a fact that the Gangotri Station has been constructed for scientific research? I would like to know whether oxygen is available there or not.

डा. मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन् इस समय वहां पर हमारा जो केन्द्र काम कर रहा है उसका नाम मैत्री है। दक्षिण गंगोत्री नामक केन्द्र, हमारा पहला केन्द्र था। उसका जीवन 1988 में समाप्त हो गया है। इसके बाद दक्षिणी गंगोत्री नाम का पहला केन्द्र न होकर, मैत्री नाम से दूसरा केन्द्र काम कर रहा है। इसके भी जीवन का अब समाप्त होने का समय आ गया है। इसका भवन अब जीर्ण-शीर्ण हो गया है। जो इसके बहुत सारे उपकरण रखे थे, वे अब पुराने हो गए हैं। हमें अंटार्कटिका में अनुसंधान के काफी नये आयाम मिले हैं इसलिए एक नए केंद्र की स्थापना की बात हो रही है तथा साथ ही इस पुराने केंद्र को सुदृढ़ करके इसका उपयोग कर सकें, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। जैसे ही इसका विवरण पूरा होगा, डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी, हम इस पर निर्णय लेंगे क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना पर हमें